tv भारतवर्ष
सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

स्पेन के खिलाफ अपना सबकुछ झोंकने के लिए तैयार-मेसी

Page-04

सिनेमा जगत की बेहतरीन प्रतिभाओं को मिला सम्मान

Page-05

TMC में बढ़ी अंदरूनी कलह बागियों को अभिषेक बनर्जी की खुली चुनौती

राजस्थान के जैसलमेर जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। भारतीय सेना के 92 वर्षीय रिटायर्ड अधिकारी, कैप्टन चुन्नीलाल ने आरोप लगाया है कि उनकी जानकारी के बिना धोखे से उनकी जमीन को गिरवी रख दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया और बाद में बेच भी दिया गया। कैप्टन चुन्नीलाल देश के एक सच्चे वीर हैं, जिन्होंने चीन के साथ 1962 के युद्ध और पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 के युद्धों में देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। पूर्व कैप्टन चुन्नीलाल ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि सेना से रिटायर होने के बाद वह बस्सी आ गए थे। उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट से पहले उन्होंने कारगिल युद्ध में भी अपनी सेवाएं दी थीं और वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लड़े थे। उन्होंने बताया, "हिमाचल प्रदेश के पास हमारे परिवार की बहुत उपजाऊ खेती की जमीन थी। लेकिन सरकार ने पोंग बांध परियोजना के लिए हमारी जमीन ले ली। उस समय जो मुआवजा मिला, वह काफी नहीं था। हमें आश्वासन दिया गया कि बेघर हुए परिवारों को राजस्थान में जमीन दी जाएगी। इसके बाद मुझे मोहनगढ़ में जमीन दी गई। जब मैं पहली बार वहां पहुंचा, तो चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। सालों की कड़ी मेहनत के बाद हमने उस बंजर जमीन को सुधारा और धीरे-धीरे वह उपजाऊ बन गई।" कैप्टन चुन्नीलाल ने आरोप लगाया कि इतने सालों की खून-पसीने की मेहनत के बाद, कुछ लोगों ने जाली दस्तावेज तैयार किए और उनके हमशक्ल को खड़ा करके उनकी जमीन धोखे से बेच दी। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। 92 वर्ष से अधिक की उम्र होने के कारण उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उनके मामले की सुनवाई हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर कर दी जाए, ताकि वे आसानी से कोर्ट जा सकें और उन्हें न्याय मिल सके।

सोनम वांगचुक पर बढ़ा सियासी संग्राम
अन्ना हजारे ने सरकार से की बातचीत की अपील

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के मुद्दे पर केंद्र सरकार से संवाद शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बातचीत सबसे प्रभावी रास्ता होता है और सरकार को वांगचुक की मांगों पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। हजारे ने कहा कि सरकार को उनकी सहनशक्ति की परीक्षा लेने के बजाय उनकी मांगों पर "हां" या "ना" में जवाब देना चाहिए और बातचीत के जरिए समाधान तलाशना चाहिए।सोनम वांगचुक इन दिनों दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शनिवार को उनकी भूख हड़ताल का 21वां दिन था। इस बीच दिल्ली पुलिस उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल ले गई।दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के उद्देश्य से की गई। वहीं, आंदोलन से जुड़े लोगों और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वांगचुक को उनकी इच्छा के विरुद्ध अस्पताल ले जाया गया। कुछ छात्रों ने यह भी दावा किया कि प्रदर्शन स्थल पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, हालांकि इस संबंध में पुलिस की ओर से अलग पक्ष रखा गया है।प्रदर्शन का समर्थन कर रहे संगठन के प्रतिनिधियों का आरोप है कि हाई कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करते हुए पुलिस ने कार्रवाई की। उनका कहना है कि अदालत ने केवल वांगचुक के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए थे और उनकी हालत गंभीर होने की स्थिति में ही आगे की कार्रवाई का प्रावधान था। आंदोलनकारियों का दावा है कि वांगचुक की मेडिकल टीम लगातार उनकी जांच कर रही थी और उनकी स्वास्थ्य स्थिति स्थिर थी।अन्ना हजारे की यह अपील 2011 के उनके ऐतिहासिक जनलोकपाल आंदोलन की याद भी दिलाती है, जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबा अनशन किया था। उनका मानना है कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज को संवाद के माध्यम से सुना जाना चाहिए और सरकार को संवेदनशीलता के साथ समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए।फिलहाल सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। वहीं, उनकी अस्पताल ले जाने की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज हो गई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत की कोई पहल होती है या नहीं।

मॉनसून सत्र से पहले NCPI सांसदों को केंद्र का न्योता

संसद के मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बागी तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेताओं और नवगठित नेशनल सिटिज़न्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के सांसदों को सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने NCPI के वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय को पत्र लिखकर आगामी सत्र के दौरान संसद में होने वाले विधायी कार्यों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है।अपने पत्र में किरेन रिजिजू ने उल्लेख किया कि सुदीप बंदोपाध्याय और 19 अन्य सांसद हाल ही में NCPI में शामिल हुए हैं तथा उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अपने नए दल को आधिकारिक मान्यता देने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि यह मामला फिलहाल लोकसभा अध्यक्ष के विचाराधीन है। इसके बावजूद संसदीय परंपरा के तहत उन्हें सर्वदलीय बैठक में भाग लेने का निमंत्रण दिया गया है।रिजिजू ने सभी दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि बैठक में आगामी मॉनसून सत्र के विधायी एजेंडे और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने NCPI के चीफ व्हिप के रूप में नामित सुदीप बंदोपाध्याय और डॉ. काकोली घोष दस्तीदार से भी बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह किया है।सर्वदलीय बैठक 19 जुलाई को संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित होगी। इस बैठक में सरकार अपने प्रस्तावित विधेयकों और संसदीय कार्यसूची की जानकारी देगी, जबकि विपक्षी दल विभिन्न राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों को उठाने की तैयारी में हैं।

उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका
लोकसभा स्पीकर ने 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को दी मान्यता

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के छह बागी सांसदों के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को आधिकारिक मान्यता दे दी है। इसके साथ ही लोकसभा में ये सभी सांसद अब औपचारिक रूप से शिंदे गुट के सदस्य माने जाएंगे। इस फैसले को एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता और उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।जानकारी के अनुसार, छह सांसदों ने हाल ही में लोकसभा सचिवालय में आवेदन देकर शिंदे गुट में अपने विलय को मान्यता देने की मांग की थी। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इस निर्णय के बाद संसद में शिंदे गुट की स्थिति और मजबूत हो गई है, जबकि शिवसेना (यूबीटी) की संसदीय ताकत में कमी आई है।इस घटनाक्रम के बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि

उनके साथ जुड़े सांसद किसी निजी लाभ या स्वार्थ के कारण नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हर राजनीतिक फैसले को पैसे से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह उनकी सोच है। शिंदे ने दावा किया कि सांसद अपने क्षेत्रों के विकास और जनता की बेहतर सेवा के उद्देश्य से उनके साथ आए हैं।उन्होंने यह भी बताया कि इन सांसदों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कराई गई है, ताकि उनके संसदीय क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों को गति मिल सके। शिंदे ने भरोसा जताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उनके क्षेत्रों में लंबित परियोजनाओं को पूरा करेगी।वहीं, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। विपक्ष इसे राजनीतिक दबाव और दल-बदल की राजनीति बता रहा है, जबकि शिंदे गुट इसे विकास और जनहित की राजनीति का हिस्सा बता रहा है। आने वाले दिनों में इस फैसले का असर राज्य की राजनीति और शिवसेना की अंदरूनी रणनीति पर साफ दिखाई दे सकता है।

प्रधानमंत्री मोदीके साथ मंच पर दिखे मनीष तिवारी

सीनियर कांग्रेस नेता और सांसद मनीष तिवारी ने 18 जुलाई को सरकारी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मौजूदगी को लेकर हो रही आलोचना का जवाब दिया। 'X' पर इस मुद्दे पर बात करते हुए तिवारी ने कहा कि मैंने हमेशा विकास की ज़रूरतों को पार्टी की राजनीति से ऊपर रखने की कोशिश की है... मैं ऐसा ही हूँ, चाहे कोई कुछ भी सोचे! ये टिप्पणियां 17 जुलाई को तिवारी के एक हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आईं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने चंडीगढ़ और तिवारी के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। तिवारी ने 24 अगस्त, 2022 की एक घटना का ज़िक्र किया, जब उन्होंने पार्टी के मतभेदों से ऊपर उठकर इलाके की तरक्की को प्राथमिकता दी थी। उन्होंने न्यू चंडीगढ़ में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया था—एक ऐसी सुविधा जिसे उन्होंने इस इलाके के हज़ारों कैंसर मरीज़ों के लिए एक अहम जीवन-रेखा बताया था। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मैंने हमेशा विकास की ज़रूरतों को पार्टी की राजनीति से ऊपर रखने की कोशिश की है।

अहमदाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 8 लोगों की मौत, कई घायल

गुजरात के अहमदाबाद में रविवार को एक अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। हादसे में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए। धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज़ करीब पांच किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट के बाद फैक्ट्री में आग लग गई और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।यह घटना रामोल-गात्रद रोड स्थित वस्त्राल इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) कैंप के पीछे संचालित एक कथित अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि आसपास की कई इमारतें भी इसकी चपेट में आ गईं और इलाके में धुएं का गुबार फैल गया।धमाके की आवाज सुनते ही पास में स्थित RAF कैंप के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही

राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। जवानों ने मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने और घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनमें से चार लोगों को एल.जी. अस्पताल और तीन को असरवा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य घायलों का भी विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।हादसे की सूचना मिलते ही अहमदाबाद नगर निगम की फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं। पांच से अधिक फायर टेंडरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग पूरी तरह बुझाने के बाद भी दोबारा किसी विस्फोट की आशंका को देखते हुए कूलिंग ऑपरेशन जारी रखा गया।

हिन्दी जगत महामंच
www.tvbharatvarsh.in
tv भारतवर्ष
सच्ची खबर, सीधे आपके लिए
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ई-पेपर
प्रदेश का नं. 1
प्रतिष्ठित हिन्दी न्यूज़
ई-पेपर

विज्ञापन दर

साईज	विजिटिंग कार्ड	क्वाटर पेज	हाफ पेज	फुल पेज (अंदर)	फुल पेज (कवर 2-3)	फुल पेज (कवर 4- अंतिम)	(फ्रंट पेज)
रेट	₹ 3000	₹ 6000	₹ 10,000	₹ 20,000	₹ 25,000	₹ 30,000	₹ 100000

8601780000

क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा गंभीर चुनौती बनती जा रही है?

इस मुद्दे को लेकर भारत भी पहले अपनी चिंता जता चुका है। 23 जून को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदू देवी-देवताओं और उनकी प्रतिमाओं के कथित अपमान की खबरें चिंताजनक हैं, जिनके कारण विरोध प्रदर्शन हुए।

बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित नेशनल प्रेस क्लब के बाहर शुक्रवार को हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का आयोजन बांग्लादेश हिंदू-बौद्ध-ईसाई एकता परिषद ने किया। प्रदर्शनकारियों ने हिंदू युवक हरिदास चंद्र तरणी दास की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोप में फंसाया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दास ने उत्तरी बांग्लादेश के गाइबांधा जिले के पलाशबाड़ी क्षेत्र में भगवान राम की 81 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की पहल की थी। उनका आरोप है कि इसी के बाद उन्हें निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। एकता परिषद के महासचिव मणिंद्र कुमार नाथ ने कहा कि संगठन हरिदास चंद्र तरणी दास की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा, 'सरकार ने दो-तीन दिन पहले उन्हें इस आरोप में गिरफ्तार किया कि उन्होंने पलाशबाड़ी में भगवान राम की प्रतिमा बनवाई। हम इस तरह की गिरफ्तारी को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते।' मणिंद्र कुमार नाथ ने आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों से बांग्लादेश में गैर-मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगातार हमले और उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा, पिछले वर्ष पूरे बांग्लादेश में करीब 3,000 घटनाएं हुईं। इनमें 66 लोगों की हत्या कर दी गई और कई मंदिरों पर कट्टरपंथियों ने हमले किए। यह बेहद दुखद है और हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।' प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हरिदास चंद्र तरणी दास को अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उनका आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला धार्मिक निर्माण कार्य को रोकने के उद्देश्य से लगाया गया है। यह मामला पिछले महीने गाइबांधा जिले में एक इस्लामी प्रदर्शन के दौरान भगवान राम की प्रतिमा के अपमान के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के कुछ समय बाद सामने आया है। एकता परिषद के वरिष्ठ नेता सुब्रत चौधरी ने प्रदर्शन के दौरान अंतरिम सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा,'देश में आपसी सौहार्द का माहौल बना था। ऐसे में यह घटना किसने कराई और सरकार को शर्मिंदा करने की कोशिश किसने की, इसका पता लगाया जाना चाहिए। हम सरकार से इस मामले में तुरंत उचित कार्रवाई की मांग करते हैं।' सुब्रत चौधरी ने कहा कि हरिदास चंद्र तरणी दास को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने धर्म का अपमान करने वालों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई नहीं की और गिरफ्तार युवक को रिहा नहीं किया, तो पूरे बांग्लादेश में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आखिर किसके निर्देश पर हरिदास चंद्र तरणी दास को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा, 'सरकार यह बताए कि इस कार्रवाई के पीछे कौन लोग हैं। चाहे वे कितने ही बड़े प्रशासनिक अधिकारी क्यों न हों, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।' एकता परिषद के नेताओं ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय अब अपने धार्मिक अधिकारों को दबाने के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यदि गिरफ्तार युवक को जल्द रिहा नहीं किया गया तो बांग्लादेश का सनातन, बौद्ध और ईसाई समुदाय मिलकर देशव्यापी आंदोलन करेगा।

ईरान ने अमेरिका से लिया बदला कई लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया

अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुई जंग ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है। इस बार हमले इतने डेंजर हैं कि भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ घंटे पहले ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए अमेरिका ने स्ट्राइक की थी। इस हमले में भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर को तगड़ा नुकसान पहुंचा। जिसमें आठ लोगों की मौत हुई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन अब ईरान ने अमेरिका से ऐसा बदला लिया है कि जिसने ट्रंप को भी हिलाकर रख दिया है। पहली बार ईरान के रौद्र रूप को देखकर सब हैरान हैं। दरअसल हमलों का बदला लेते हुए ईरान ने अमेरिका के कई लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया है। वो फाइटर जेट्स जिन पर ट्रंप सबसे ज्यादा गुरूर करते थे। अब इन्हीं लड़ाकू विमानों को एक झटके में ही ईरान ने धुआधुआ करते हुए मिट्टी में मिला दिया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में खड़े हुए कई अमेरिकी सैन्य फाइटर जेट्स को बैलस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। जिसमें कई अमेरिकी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट तबाह हो गए। इसके अलावा कई और को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। इस हमले में कई बैलेस्टिक मिसाइलों बड़ी संख्या में ड्रोंस का इस्तेमाल हुआ है। दरअसल ईरान ने यह हमला उन हमलों के जवाब में किया है जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने हमलों को बढ़ाते हुए पुलों एनर्जी साइट्स को निशाना बनाया और साथ ही चाबहार पोर्ट पर एक टावर गिरा दिया। चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। इस टावर को गिराने के लिए अमेरिका ने एक नहीं तीन-तीन बार हमले किए।

ग्वाटेमाला सीमा के पास 7.3 तीव्रता के अत्यंत शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए

सोनम वांगचुक के समर्थन में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन गूंज उठी

भारत की परीक्षा प्रणाली और NEET में हुई कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छिड़ी जंग अब सात समंदर पार पहुंच चुकी है। 28 जून से दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठे पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक के समर्थन में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन गूंज उठी है। दो बड़े एक्टिविस्ट ग्रुप्स ने एकजुट होकर न सिर्फ वांगचुक के सुर में सुर मिलाया, बल्कि सीधे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी है। हिंदूज़ फ़ॉर ह्यूमन राइट्स और आज़ादी प्रोजेक्ट के सदस्य भारतीय दूतावास के पास महात्मा गांधी की मूर्ति के पास जमा हुए। उन्होंने वांगचुक के समर्थन में प्लेकार्ड उठाए और भारत सरकार के खिलाफ़ नारे लगाए। यह विरोध प्रदर्शन 'हिंदूज़ फ़ॉर ह्यूमन राइट्स' की उस

सार्वजनिक अपील के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने भारत सरकार से वांगचुक और भूख हड़ताल पर बैठे अन्य प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने को कहा था। स हफ़्ते की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक खुले पत्र में 'हिंदूज़ फ़ॉर ह्यूमन राइट्स' ने कहा सरकार को प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहिए, उनके बताए गए परीक्षा और गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर ठोस जवाब देना चाहिए और जवाबदेही तय करने के लिए एक भरोसेमंद और समय-सीमा वाली प्रक्रिया बनानी चाहिए। हिंदूज़ फ़ॉर ह्यूमन राइट्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुनीता विश्वनाथ ने एक बयान में कहा कि सरकार को अभी प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहिए, उन कमियों का जवाब देना चाहिए जिनकी वजह से वे यहाँ तक पहुँचे हैं और उदासीनता के कारण किसी की जान जाने से पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए। संगठन ने वांगचुक और भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से अपनी सेहत और ज़िंदगी को प्राथमिकता देने की अपील भी की। इसमें कहा गया,उनकी चिंताओं को पूरे भारत और दुनिया भर के लोगों ने सुना है। अपनी मांगों की गंभीरता दिखाने के लिए उन्हें अपनी सेहत दांव पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए।"

रूस-यूक्रेन युद्ध : यूक्रेन ने रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए

यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी 2022 से जारी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देश तब से एक-दूसरे पर हमले कर रहे है। ऐसे में इसकी सबसे बड़ी कीमत दोनों देशों के आम नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। इसी बीच शनिवार को यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों में ड्रोन हमले किए। इन हमलों में सात वेयरहाउस कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। इसके अलावा मॉस्को क्षेत्र के एक तेल डिपो में भी आग लग गई। तांबोव क्षेत्र के गवर्नर एवगेनी पेरविशोव ने बताया कि मॉस्को से करीब 475 किलोमीटर दूर स्थित कोतोव्स्क शहर में यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। हमला रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्डबेरीज के गोदाम पर हुआ। इस हमले में 25 लोग घायल हो गए। पेरविशोव ने कहा कि रात की शिफ्ट में काम कर रहे सात कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि रूसी एयर डिफेंस ने 28 ड्रोन को पहले ही मार गिराया। उनका कहना है कि यदि सभी ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते, तो मृतकों और घायलों की संख्या कहीं अधिक हो सकती थी। मॉस्को क्षेत्र के इलेक्ट्रोस्टल शहर में वाइल्डबेरीज़ के एक अन्य वेयरहाउस पर भी ड्रोन हमला हुआ। इस घटना में 24 लोग घायल हो गए। वाइल्डबेरीज़ की सह-संस्थापक और CEO तात्याना किम ने इसे कंपनी और रूस, दोनों के लिए बेहद दुखद रात बताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। मॉस्को क्षेत्र के नोगिंस्क शहर में ड्रोन का मलबा गिरने से एक तेल डिपो में आग लग गई। इस घटना में दो लोग घायल हुए हैं। एहतियात के तौर पर पास के एक मैटरनिटी अस्पताल को भी खाली करा लिया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान दोनों पक्ष लगातार एक-दूसरे पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं। शनिवार को हुआ यह हमला हाल के दिनों में रूस पर हुए बड़े ड्रोन हमलों में से एक माना जा रहा है।

आमिर मतीन ने अपने देश की सरकारों को घेरा वहीं भारत को उन्होंने सराहा

पाकिस्तान के जाने-माने विश्लेषक आमिर मतीन ने अपने देश की सरकारों को उर्जा सुरक्षा पर काम ना किए जाने के लिए घेरा है। वहीं भारत को उन्होंने सराहा है। उन्होंने कहा कि भारत की रिफाइनरी ना सिर्फ अपने देश को तेल दे रही हैं बल्कि बेचकर मुनाफा भी कमा रही हैं। वहीं पाकिस्तान में तेल की कमी से हाहाकार हो गया है। ईरान में युद्ध के चलते होर्मुज स्ट्रेट बंद होने और दुनियाभर में तेल-गैस की किल्लत से जुड़े सवाल पर आमिर मतीन ने यह कहा है। ईरान ने अमेरिकी हमलों की जवाबी कार्रवाई के तौर पर होर्मुज स्ट्रेट को बंद किया हुआ है, जो खाड़ी देशों से एशिया में तेल और गैस पहुंचाने का बेहद अहम रास्ता है। इसने दुनिया के बड़े हिस्से खासतौर से भारत-पाकिस्तान और एशियाई मुल्कों को प्रभावित किया है। इसी संकट पर बात करते हुए आमिर मतीन ने भारत और पाकिस्तान की तुलना की है। आमिर मतीन ने तेल-गैस को लेकर चल रहे संकट के मुद्दे पर बोलते हुए टीवी92 के एक कायक्रम में कहा कि क्राइसिस है और इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। सवाल ये है कि आपने इसके लिए क्या तैयारी की थी और यहां तक कि ये पूरा मामला शुरू होने के बाद भी क्या कदम उठाए हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार की कोशिशें जीरों हैं। मतीन ने आगे कहा, 'हमारे पड़ोस में भारत है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियां हैं। खासतौर से गुजरात में बड़ी रिफाइनरी हैं, जो समुद्र से लगा हुआ सूबा है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीद को लेकर कई तरह प्रतिबंध भारत पर लगाए हैं। हाल ही में हमने देखा कि अमेरिका 100 फीसदी टैरिफ की बात कर रहा है। इसके बावजूद भारत में बढ़िया काम हो रहा है।' आमिर मतीन ने दावा किया कि प्रतिबंधों के बावजूद भारत ना सिर्फ रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है बल्कि उसे रिफाइन भी कर रहा है। वहां रिफाइन किया हुआ तेल वापस रूस और दुनिया को बेचकर भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। भारत की रिफाइनरियां सिर्फ रूसी तेल से ही 12 से 17 अरब डॉलर तक कमा रही हैं। पाकिस्तानी सरकार को घेरते हुए मतीन ने कहा कि हमारे देश में पिछले बीस-तीस सालों से हर बिजली बिल पर टैक्स लगाया जा रहा है। इस टैक्स के पैसे को रिफाइनरियों को देने की बात की जाती है।

संपादक की कलम से

महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां राजनीतिक समीकरण किसी भी वक्त बदल सकते हैं। एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय की चर्चाओं ने न केवल राज्य की राजनीति को गर्मा दिया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने आधिकारिक तौर पर इस पर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन लगातार हो रही बैठकों और राजनीतिक गतिविधियों ने इन अटकलों को बल जरूर दिया है।अगर इन चर्चाओं में सच्चाई है, तो सवाल यह उठता है कि क्या यह विचारधारा का मेल होगा या फिर राजनीतिक मजबूरी का परिणाम? पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह दलों के भीतर टूट और नए गठबंधन बने हैं, उससे मतदाताओं के सामने भी यह सवाल खड़ा होता है कि चुनाव के समय किए गए वादे और बाद में बनने वाले राजनीतिक समीकरणों में कितना सामंजस्य बचा है।दूसरा महत्वपूर्ण पहलू संसद में आने वाले महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे संविधान संशोधन विधेयकों का है। ऐसे विधेयकों को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होता है। यदि किसी दल का समर्थन केवल संसदीय संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से लिया जाता है, तो विपक्ष स्वाभाविक रूप से इसे राजनीतिक गणित कहेगा। वहीं सरकार इसे राष्ट्रीय हित में व्यापक सहमति बनाने का प्रयास बता सकती है। लोकतंत्र में दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलील रखते हैं, लेकिन अंतिम कसौटी पारदर्शिता और जनहित ही होनी चाहिए।एनसीपी के भीतर भी मतभेदों की खबरें सामने आ रही हैं। यदि किसी राजनीतिक दल में विलय को लेकर अलग-अलग राय है, तो यह उस दल का आंतरिक विषय है। लेकिन यदि विलय होता है, तो नेतृत्व, संगठन और कार्यकर्ताओं के भविष्य को लेकर कई नए सवाल खड़े होंगे। सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि क्या दोनों गुट अपने पुराने राजनीतिक मतभेदों को वास्तव में पीछे छोड़ पाएंगे।महाराष्ट्र की राजनीति का असर केवल राज्य तक सीमित नहीं रहता। देश की आर्थिक राजधानी होने के कारण यहां के राजनीतिक फैसलों का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति और निवेश के माहौल पर भी पड़ता है। इसलिए हर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम पूरे देश की निगाहों में रहता है।फिलहाल स्थिति अटकलों के दौर में है। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति और संसद के मानसून सत्र—दोनों पर देश की नजरें टिकी रहेंगी। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि राजनीतिक फैसले स्पष्टता, जवाबदेही और जनता के विश्वास को ध्यान में रखकर लिए जाएं, न कि केवल सत्ता के अंकगणित के आधार पर।

एनडीए को मजबूत करने की कवायद? एनसीपी के दोनों गुटों को साथ लाने की कोशिश

इन सभी अटकलों के बीच एनसीपी और एनसीपी (एसपी) दोनों ने ही आधिकारिक रूप से विलय पर किसी बातचीत से इनकार किया है। एनसीपी (शरद गुट) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को स्पष्ट कहा कि अजित पवार के जीवित रहते विलय पर चर्चा हुई थी, लेकिन उनके निधन के बाद दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया और वहीं यह मामला समाप्त हो गया।

महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा (BJP) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को और मजबूत करने के लिए एनसीपी (NCP) के दोनों गुटों के विलय के पक्ष में है और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली एनसीपी सत्ताधारी एनडीए का हिस्सा है, जबकि शरद पवार की एनसीपी (एसपी) विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन में शामिल है। हालांकि, सुनेत्रा पवार और उनके बड़े बेटे व राज्यसभा सांसद पार्थ पवार इस संभावित विलय के खिलाफ बताये जा रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार आगामी संसद सत्र में महिला आरक्षण लागू करने और परिसीमन (Delimitation) से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने की तैयारी में है। ऐसे विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। इसी वजह से भाजपा नेतृत्व दोनों एनसीपी गुटों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि दोनों पक्षों को केंद्र सरकार में एक-एक मंत्री पद देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार पार्टी के विलय के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि यदि दोनों दल एक हो गए तो शरद पवार और सुप्रिया सुले फिर से पार्टी पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि यदि विलय अपरिहार्य हुआ तो सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष दोनों पदों पर बनी रहने की मांग कर सकती हैं। दूसरी ओर, पार्टी के ही कई अन्य विधायक और वरिष्ठ नेता इस विलय के समर्थन में लामबंदी करने में जुटे हैं। गुरुवार को पार्थ पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। वहीं इससे पहले शरद पवार नीत एनसीपी (एसपी) के जयंत पाटिल मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, जहां सुनेत्रा पवार खेमे के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी मौजूद थे। इसके अलावा जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की। इन बैठकों के बाद दोनों दलों के विलय की अटकलों को और बल मिल गया। दरअसल, सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र को देखते हुए केंद्र सरकार संविधान संशोधन विधेयक (महिला आरक्षण और परिसीमन लागू करने संबंधी) को दोबारा पेश करने की तैयारी में है, जो पिछले सत्र में जरूरी समर्थन न मिलने के कारण पास नहीं हो सका था। लोकसभा की वर्तमान ताकत 540 है, जहां दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 सांसदों की जरूरत है। एनडीए के पास फिलहाल 319 का आंकड़ा है। अगर शरद पवार की पार्टी का समर्थन मिलता है, तो यह संख्या 327 हो जाएगी। बाकी 33 की कमी को पूरा करने के लिए भाजपा सरकार कुछ दलों के वॉकआउट या अनुपस्थित रहने की रणनीति अपना सकती है। रिपोर्ट्स का कहना है कि सुनेत्रा पवार की एनसीपी के कुछ विधायक विलय के पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यदि शरद पवार एनडीए में शामिल होते हैं तो और विधायक विलय के पक्ष में आ सकते हैं।

सरकार का पूरा फोकस महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर

सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में वन नेशन, वन इलेक्शन बिल नहीं आएगा। सूत्रों के अनुसार सरकार का मानना है कि वन नेशन, वन इलेक्शन बिल के लिए अभी टाइम है, क्योंकि इसका टारगेट 2029 का चुनाव है और उसमें 3 साल का वक्त है। फिलहाल सरकार का फोकस महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर है। डिलिमिटेशन बिल इस सत्र में आएगा या नहीं। इस बारे में अगले एक-दो दिन में स्थिति साफ हो सकती है। संसद के मॉनसून सेशन को लेकर शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में राजनाथ सिंह के अलावा अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू, जेडीयू नेता ललन सिंह, टीडीपी नेता राम मोहन नायडू और आरएलडी से जयंत चौधरी शामिल हुए। सरकार का मानना है कि महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर विपक्षी पार्टियों में से भी कई दल बिल के पक्ष में रहेंगे और कांग्रेस अलग-थलग पड़ जाएगी। इस बीच विपक्षी पार्टियां भी मॉनसून सेशन के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं। डीएमके प्रेसीडेंट एमके स्टालिन इन दिनों लंदन में हैं। वहीं से उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। स्टालिन से चर्चा करने के बाद डीएमके के नेताओं ने कहा कि अगर डिलिमेटेशन बिल अपने मौजूदा प्रारूप में ही आता है तो वो इसका विरोध करेंगे। सरवनन अन्नादुरई कह रहे थे कि डिलिमिटेशन बिल तमिलनाडु के हितों के खिलाफ है। अगर बिल को उसके मौजूदा प्रारूप में पास करवाया गया तो इससे दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। देखना होगा कि सरकार इसमें कोई बदलाव करती है या नहीं, लेकिन अगर बिल से तमिलनाडु को नुकसान हुआ तो डीएमके इसका विरोध करेगी। परिसीमन बिल का सबसे ज्यादा विरोध साउथ की पार्टियां ही कर रही हैं। दक्षिण भारत के पांच राज्यों से आने वाले नेताओं को लग रहा है कि इससे उन्हें नुकसान होगा। तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से कांग्रेस सांसद कार्ती चिदंबरम ने भी कहा कि परिसीमन बिल से नॉर्थ और साउथ के बीच गैप बढ़ जाएगा। उन्होंने एक और समस्या का जिक्र किया। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि अभी लोकसभा में 543 सांसद हैं फिर भी बहुत कम लोगों को बोलने का मौका मिलता है। अगर साढ़े आठ सौ सीटें हो जाएंगी, तो फिर ज्यादातर सांसद मूक दर्शक बनकर रह जाएंगे।

'असत्य और हिंसा सरकार के मूल सिद्धांत'— सोनम वांगचुक मामले पर राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली के जंतर-मंतर से हटाए जाने की आलोचना की, जहां वे भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने केंद्र सरकार पर देश भर के छात्रों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने वाली आवाजों को दबाने का आरोप लगाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के मूल सिद्धांत असत्य और हिंसा हैं। गांधी ने कहा कि जब सोनम वांगचुक जी अहिंसक भूख हड़ताल पर थे, तब उन्हें जंतर-मंतर से हटाना गलत है। वांगचुक के विरोध को शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी व्यापक चिंताओं से जोड़ते हुए गांधी ने कहा कि पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों की आत्महत्या भारत के भविष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से हैं। उन्होंने #ChhatronKiGoonj हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए कहा कि कोई भी ताकत भारत के छात्रों को और हममें से उन लोगों को जो उनसे प्यार करते हैं और उनमें भरोसा रखते हैं। इन मुद्दों को उठाने से नहीं रोक सकती। यह बयान देहरादून में 'छात्रों की गूंज' रैली को गांधी के संबोधित करने के एक दिन बाद आया है, जहां उन्होंने भारत की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि किसी भी राजनीतिक दल या संगठन का शिक्षण संस्थानों पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए और बार-बार होने वाले पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए व्यापक राजनीतिक सहमति बनाने का आह्वान किया था। रैली में गांधी ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने से लगभग 75 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि यह समस्या कई हितधारकों से जुड़े भ्रष्ट तंत्र के कारण है, जिनमें कोचिंग सेंटर, परीक्षा केंद्र, प्रश्नपत्र तैयार करने वाले, परिवहनकर्ता, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय शामिल हैं। उन्होंने देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार की वकालत करते हुए मौजूदा मॉडल को पुराना और छात्रों के बजाय परीक्षा पर अत्यधिक केंद्रित बताया। गांधी के अनुसार, वर्तमान परीक्षक-केंद्रित और सरकार-केंद्रित दृष्टिकोण को छात्र-केंद्रित ढांचे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें सुरक्षित प्रश्न बैंक और प्रौद्योगिकी-आधारित यादृच्छिक प्रश्नपत्र हों, जो जीएमएटी जैसी अंतरराष्ट्रीय मानकीकृत परीक्षाओं के समान हों।

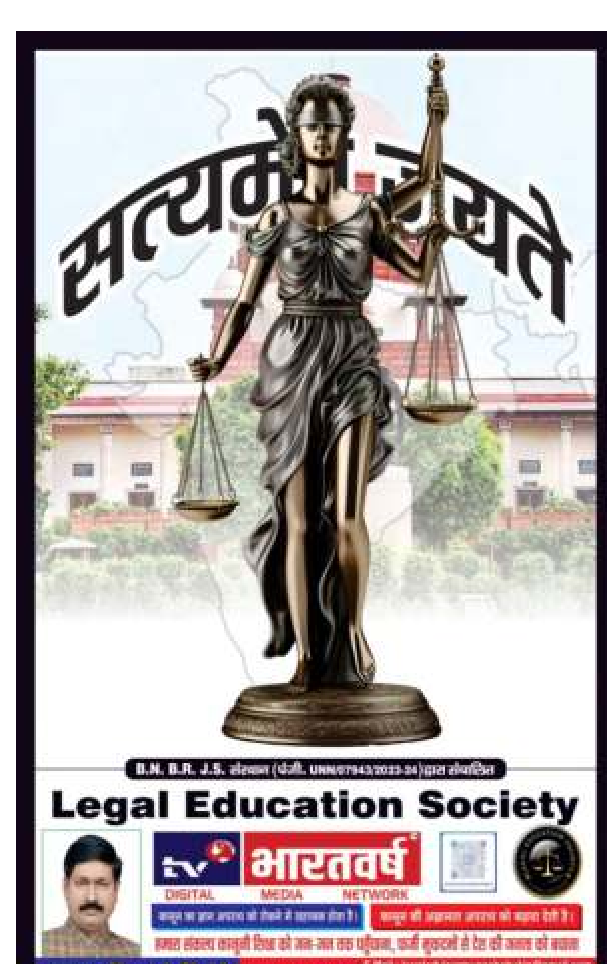

NEET क्वालिफाई छात्राओं के लिए सुनहरा मौका

इंडियन आर्मी में BSc नर्सिंग के जरिए बनें ऑफिसर

इंडियन आर्मी नीट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए शानदार मौका लाई है। आर्म्ड मेडिकल फोर्सेस मेडिकल सर्विसेस (AFMS) ने बीएससी नर्सिंग कोर्स-2026 में आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो महिलाएं देशसेवा करने के साथ आर्मी में करियर बनाना चाहती हैं, खासतौर से उनके लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स पूरा करने के बाद कैंडिडेट्स को सेना में ही परमानेंट कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत पोस्टिंग मिलेगी। vआर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस (AFMS) में बीएससी नर्सिंग कोर्स करने लिए केवल महिलाएं ही आवेदन की पात्र होंगी। इस स्पेशल एंट्री के लिए कैंडिडेट्स आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। शॉर्टलिस्टिंग अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग के लिए दिल्ली कैंट मं मौजूद बेस हॉस्पिटल पहुंचना होगा। आर्मी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए योग्यता

12वीं पास : कैंडिडेट् ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी (बॉटनी एंड ज्यूलॉजी) और इंग्लिश 50 प्रतिशत अंकों के साथ (10+2) सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पहले अटेंम्ट में पास की हो या इसके समकक्ष दूसरा एग्जाम उत्तीर्ण किया हो।

नीट: कैंडिडेट ने एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा क्वालिफाई की हो.

उम्र सीमा: अभ्यर्थी का जन्म 1 अक्टूबर 2001 से 30 अक्टूबर 2009 के बीच हुआ हो। दोनों की तिथियां भी काउंट होगी।

जेंडर: केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकेंगी। पुरुष अभ्यर्थी एप्लिकेशन फॉर्म भरने के पात्र नहीं होंगे।

हाइट: न्यूनतम 152 सेमी हाइट होनी चाहिए। हिल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 147 सेमी लंबाई भी स्वीकार होगी। अभ्यर्थियों का वजन भी उनकी हाइट के मुताबिक होना चाहिए। आर्मी बीएससी नर्सिंग के लिए सेलेक्शन क्राइटेरिया

शॉर्टलिस्टिंग: नीट यूजी 2026 स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स को इसके लिए चुना जाएगा उनकी लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा किया जाएग। यहां ओरिजनल सर्टिफिकेट भी साथ ले जाने होंगे।

टेस्ट: जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश (ToGIGE) टेस्ट में कंप्यूटर पर होगा। जिसमें 40 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल आएंगे। हर सवाल 02 नंबर का होगा। वहीं 0.5 की निगेटिव मार्किंग भी इसे रहेगी।

साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू: ऊपर सभी स्टेज क्लियर करने के बाद सेलेक्शन बोर्ड कैंडिडेट्स को साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू के लिए बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट बुलाएगा। यहां 12वीं क्लास के कोर सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज ,करंट अफेयर्स, उनकी हॉबी आदि पर उनसे सवाल-जवाब किए जाएंगे।

मेडिकल एग्जामिनेशन:आर्मी से जुड़ने के लिए मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए अभ्यर्थियों का पूरा मेडिकल टेस्ट किया जाएगा।

फाइनल सेलेक्शन: सभी स्टेज क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की फाइनल सेलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी।

एडमिशन: चयनित अभ्यर्थियों को आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कमीशन से मान्यता मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिलेगा। बीएससी नर्सिंग का 4 साल का कोर्स पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों को आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस में परमानेंट कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में बतौर ऑफिसर पद पर तैनात किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान अभ्यर्थियों को फ्री राशन, यूनिफॉर्म, मंथली स्टाइपेंड और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। ऐसे में नीट क्लियर करने के बाद आप सीधे बीएससी करके इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। सेना की इस भर्ती से जुड़ी अन्य किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश जिला न्यायालय में 130 पदों पर भर्ती, बिना फीस करें आवेदन

कोर्ट में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश के जिला न्यायालयों में टेक्निकल मैनपावर की जरूरत है। जिसके लिए सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट भर्ती की घोषणा हुई है। इस वैकेंसी का आधिकारिक विज्ञापन भी जारी हो गया है। योग्य कैंडिडेट्स 20 जुलाई से कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट mphc.gov.in की मदद से फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की यह भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस पर की जाएगी। जिसके जरिए 130 पदों को भरा जाएगा। जो अभ्यर्थी अच्छी सैलरी वाली गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा अवसर है। क्योंकि इस पोस्ट पर चयनित अभ्यर्थियों को 7th पे कमीशन के तहत बढ़िया सैलरी मिलेगी। मध्य प्रदेश जिला कोर्ट के लिए आई इस भर्ती में आवेदन करने का कोई शुल्क तय नहीं किया गया है। एप्लिकेशन की विंडो खुलने के बाद सभी वर्ग के कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में बिल्कुल निशुल्क फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर कंप्यूटर प्रोग्राम असिस्टेंट की सरकारी नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थियों को प्रमुख रूप से चार चरणों से गुजरना होगा। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, प्रेक्टिल, इंटरव्यू और पास्ट परफॉर्मेंस। सभी को डिटेल में जानना भी जरूरी है।

स्मृति मंधाना 18 जुलाई को अपना 30वां जन्मदिन मना रही

पीवी सिंधु जापान ओपन 2026 के महिला सिंगल्स फ़ाइनल में पहली भारतीय शटलर बनीं

भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु जापान ओपन 2026 के महिला सिंगल्स फ़ाइनल में पहुँच गईं। शनिवार को सेमीफ़ाइनल में उनकी प्रतिद्वंद्वी, चीन की चेन युफ़ेई, दूसरे गेम के बीच में ही चोट के कारण मैच से हट गईं। Olympics.com के अनुसार, दुनिया में 12वें नंबर के ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ी टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नेजियम में मैच में 21-19, 15-10 से आगे चल रहे थे, तभी दुनिया के नंबर 4 खिलाड़ी और पूर्व ओलंपिक चैंपियन चेन ने हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण मैच से नाम वापस ले लिया। सिंधु अब रविवार को खिताबी मुकाबले में जापान की दुनिया की नंबर 3 खिलाड़ी अकाने यामागुची से भिड़ेंगी। यामागुची ने दूसरे सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की छठे नंबर की खिलाड़ी पुत्री कुसुमा वरदानी को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। यह फ़ाइनल, दिसंबर 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट जीतने के बाद से BWF वर्ल्ड टूर के किसी ख़िताबी मुक़ाबले में सिंधु की पहली उपस्थिति होगी। साथ ही, यह BWF सुपर 750 इवेंट में उनका पहला फ़ाइनल मुक़ाबला भी होगा। चेन के ख़िलाफ़ 8-6 के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड के साथ सेमीफ़ाइनल में उतरीं सिंधु ने मज़बूत शुरुआत की और पहले गेम में 16-11 की बढ़त बना ली। हालाँकि, चेन - जिन्होंने सिंधु को पिछली चार मुलाक़ातों में हराया था - ने वापसी करते हुए स्कोर 18-18 से बराबर कर दिया। सिंधु ने आख़िरी पलों में संयम बनाए रखा और पहला गेम 21-19 से जीत लिया। Olympics.com के अनुसार, भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे गेम में भी अपनी लय बनाए रखी और बढ़त हासिल की, लेकिन 44 मिनट के खेल के बाद चोट के कारण चेन को मुकाबला रोकना पड़ा। सिंधु ने चेन को इससे पहले 2019 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफ़ाइनल में हराया था, जहाँ उन्होंने बाद में ख़िताब भी जीता था। इस जीत के साथ, सिंधु जापान ओपन के फ़ाइनल में पहुँचने वाली पहली भारतीय शटलर बन गईं। वह इस साल टूर्नामेंट में बची हुई एकमात्र भारतीय खिलाड़ी भी हैं।

रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की खबरों पर पूरी तरह विराम

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की खबरों पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पूरी तरह विराम लगा दिया है। BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने साफ तौर पर कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को लॉर्ड्स में होने वाला तीसरा वनडे मैच रोहित शर्मा का आखिरी मैच नहीं होगा। उन्होंने मीडिया में चल रही सभी अटकलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि रोहित जब तक टीम के लिए उपयोगी हैं, तब तक देश के लिए खेलते रहेंगे। BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने PTI से कहा, "मीडिया में रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है कि रोहित रविवार को लॉर्ड्स में अपना आखिरी मैच खेलेंगे। रोहित भारतीय वनडे टीम के रेगुलर सदस्य हैं और जब तक वह टीम की योजनाओं का हिस्सा रहेंगे, तब तक देश का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो, लॉर्ड्स वनडे उनका आखिरी मैच नहीं होगा।" रोहित की हालिया फॉर्म पर सवाल उठने के बावजूद, बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने अनुभवी ओपनर का समर्थन करते हुए कहा कि सीरीज के आखिरी मैच से पहले उन पर कोई दबाव नहीं है। कोटक ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा, "देखिए, मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी पर किसी तरह का दबाव हो सकता है। वह इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि उन्हें ऐसा महसूस नहीं होगा। हां, शुरुआती दो मैचों में उन्हें रन नहीं मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। लेकिन आज भी ऐसा लग रहा था कि शायद वह अच्छी पारी खेलेंगे।

स्पेन के खिलाफ अपना सबकुछ झोंकने के लिए तैयार-मेसी

न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले जाने वाले अर्जेंटीना और स्पेन की टीम के बीच फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले अर्जेंटीना टीम के कप्तान लियोनल मेसी का बड़ा बयान सामने आया है। फाइनल मुकाबले से पहले न्यूयॉर्क में फैनेटिक्स फेस्ट में एक मंच पर खेल के दिग्गज पहुंचे थे जिसमें सुपर बाउल चैम्पियन टॉम ब्रैडी, टेनिस में सबसे ज्यादा पुरूष ग्रैंडस्लैम जीत चुके नोवाक जोकोविच और बास्केटबाल में चार बार ओलंपिक स्वर्ण जीत चुके केविन ड्यूरेंट शामिल थे। इसी में एक नाम लियोनल मेसी का भी है। मेसी ने इस दौरान साफ कर दिया कि खिताबी मैच में वह स्पेन के खिलाफ अपना सबकुछ झोंकने के लिए तैयार हैं। न्यूजर्सी में सितारों से सजी यह प्रेस कांफ्रेंस फाइनल से पहले मेसी का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम था। स्पेन के कप्तान रौड्री ने मेसी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि यह बयां करने के लिये शब्द नहीं है कि बतौर खिलाड़ी मेसी

क्या है और अर्जेंटीना के लिये उसके क्या मायने हैं। मेरी नजर में वह दुनिया का महानतम खिलाड़ी हैं। वहीं टेनिस दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने लियोनल मेसी से दबाव का सामना करने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि हार नहीं मानना चाहिये और अंत तक लड़ते रहना है। बता दें कि अभी तक विश्व कप के इतिहास में सिर्फ ब्राजील ही अकेली ऐसी टीम है जो लगातार दो बार साल 1958 और 1962 में विश्व कप को जीतने में कामयाब रही थी। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में होने वाले फाइनल मुकाबले से पहले लियोनल मेसी की स्पेन के स्टार खिलाड़ी लामिन यमाल के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें वह उन्हें जब वह काफी छोटे थे नहलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेसी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ब्राडी ने इस तस्वीर को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या क्रेजी तस्वीर है, वह बच्चा था और अब हम एक दूसरे के आमने सामने है। वहीं मेसी ने यमाल की तारीफ करने के साथ कहा कि वह इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से है।

वैभव के बारे में पाकिस्तानी क्या-क्या कर रहे सर्च?

15 साल के वैभव सूर्यवंशी का बल्ला सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बन गया है. Google Trends के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन महीनों में पाकिस्तान में वैभव को लेकर सर्च तेजी से बढ़े हैं. टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार बल्लेबाजी अब सरहद पार पाकिस्तान में भी लोगों का ध्यान खींच रही है. इसकी झलक Google Trends के ताजा आंकड़ों में भी देखने को मिल रही है.

चारपाई फिट कर निकला पूरा परिवार

बाइक को फाइव सीटर बनाने का जुगाड़

एक बाइक, बड़ा परिवार और सफर तय करने का अनोखा तरीका. पाकिस्तान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है, जिसमें एक शख्स ने बाइक के पीछे चारपाई बांधकर उसे परिवार के बैठने की जगह बना दिया.

सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान का एक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में एक शख्स ने अपनी बाइक को इस तरह मॉडिफाई किया है कि उसे देखकर लोग इसे 'देसी कार' कहने लगे हैं. बाइक के पीछे चारपाई बांध दी गई है और उसी पर परिवार के सदस्य बैठकर सफर करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक के पिछले हिस्से में लकड़ी की चारपाई मजबूती से फंसाई गई है. चारपाई के दोनों ओर परिवार के लोग संतुलन बनाकर बैठे हैं, जबकि बाइक चला रहा शख्स पूरे आराम से सड़क पर आगे बढ़ता दिखाई देता है. आसपास से गुजर रहे लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान रह जाते हैं. हालांकि यह जुगाड़ लोगों को अनोखा जरूर लगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे बेहद खतरनाक बताया जा रहा है. सड़क पर थोड़ा-सा संतुलन बिगड़ने या अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है.

सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा कि इसे देखकर लगता है कि बाइक नहीं, पूरी फैमिली कार बन गई है. दूसरे ने मजाक में कहा कि गरीबों की SUV तैयार है. वहीं कई लोगों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. एक यूजर ने लिखा कि अगर रास्ते में अचानक ब्रेक लग जाए तो क्या होगा? यह बेहद खतरनाक है.

वीडियो की पड़ताल करने पर पता चलता है कि यह पाकिस्तान का है. वहां के कई सोशल मीडिया पेजों पर इसे शेयर किया गया है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वीडियो कब और किस शहर में रिकॉर्ड किया गया था.

छापे में सोने के अंडरवियर भी मिले?

इराक में एंटी करप्शन कार्रवाई से जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इसमें दावा किया जा रहा है कि एक इराकी सांसद के घर से तलाशी में सोने के अंडरवियर बरामद हुए.

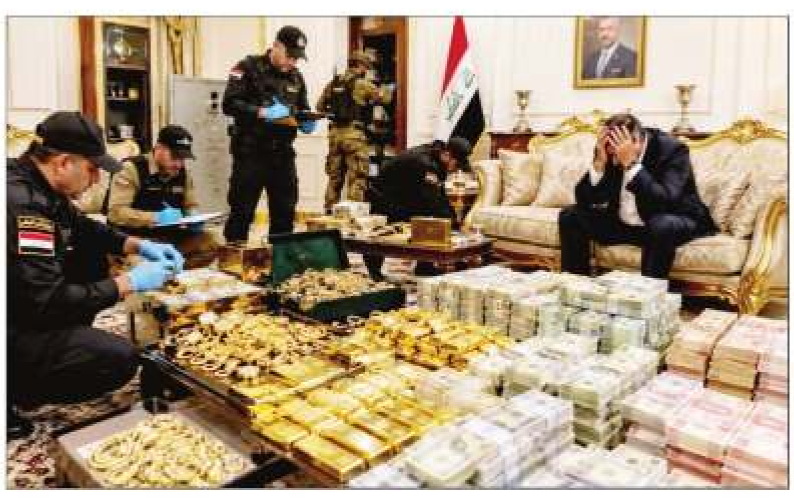

इराक में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत इराकी अधिकारियों और सांसदों के पास से भारी मात्रा में कैश, सोना और देश-विदेश में खरीदे गए संपत्तियों का पता चला है. यह पूरा एंटी करप्शन कैंपेन वहां के तेल शोधन मामलों के पूर्व उप मंत्री अदनान अल- जुमैली के कनफेशन के बाद शुरू किया गया. अल जुमैली को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था. उनके निशानदेही पर ही इराक के तेल मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों और अन्य सांसदों के घर भी छापेमारी की गई.

अब इराक के इस एंटी करप्शन कैंपेन के तहत जब्त की गई संपत्तियों और कैश की तस्वीरें और खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. अब इन वायरल तस्वीरों और खबरों के जरिए दावा किया जा रहा है कि वहां भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में एक सांसद के घर से जब्त किए जा रहे सामान में सोने के अंडरवियर और बिकनी भी मिली है. ऐसी तस्वीरें खूब वायरल हो रही है. ऐसे में चलिए जानते हैं वायरल हो रही इराक से जुड़े इन दावों के पीछे की सच्चाई क्या है? इराक में मंत्रियों और अधिकारियों के घर छापेमारी होने के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और खबर तेजी से फैली कि वहां दो सांसदों के घर से भारी मात्रा में सोना और कैश मिला है.

अकूत संपत्ति बरामद

चैनल 8 की रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा संपत्ति की बरामदगी पिछले महीने गिरफ्तार हुए इराक के पूर्व उप तेल मंत्री अदनान अल-जुमैली के घर से हुई. यहां से सुरक्षा अधिकारियों ने 11 मिलियन डॉलर कैश, 70 प्रॉपर्टी के कागज, 21 गाड़ियां और 3 किलो सोना जब्त किया. वहीं दूसरे सांसद आलिया नसीफ के घर से 15.5 मिलियन कैश और 3 किलो सोना, तेल उप मंत्री अली अल - बहादली के घर से 11 मिलियन डॉलर, लग्जरी घर और गहने बरामद किए.

एक सांसद जिनका नाम हिंद अल-अब्बासी है, उनके घर से तलाशी के दौरान 57 मिलियन डॉलर कैश, 27 किलो सोना और सोने का अंडरवियर बरामद हुआ है.

आंख फड़कने को 'अपशगुन' मान मारे थप्पड़

मध्य चीन में एक अंधविश्वासी व्यक्ति को अपनी फड़कती दाहिनी पलक पर बार-बार थप्पड़ मारना महंगा पड़ा. क्योंकि, ऐसा करने के बाद उसकी रेटिना अलग हो गई. आंख फड़कने से उसे डर था कि यह उसके लिए दुर्भाग्य का अपशगुन लेकर न आए, इसे बंद करने के लिए उसने जोर- जोर से अपनी आंख पर थप्पड़ मारे और ऐसा हुआ कि उसकी आंख की रोशनी ही चली गई. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, दाहिने आंख फड़कने पर इसे अपशगुन समझना एक लोकप्रिय चीनी कहावत से उपजी है.

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 2026 घोषित

सिनेमा जगत की बेहतरीन प्रतिभाओं को मिला सम्मान

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में विजेताओं के नाम घोषित किए। इस समारोह का लाइव प्रसारण PIB इंडिया के यूट्यूब चैनल पर किया गया। इस बार कई बेहतरीन फिल्मों, किताबों और फिल्म क्रिटिक्स (समीक्षकों) को उनके शानदार काम के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कारों की घोषणा के दौरान जूरी ने बताया कि फिल्म लेखन और सिनेमा पर आधारित पुस्तकों की कई भाषाओं में 24 एंट्रियां मिली थीं। कड़ी समीक्षा के बाद हिंदी के वरिष्ठ फिल्म समीक्षक संजीव श्रीवास्तव को बेस्ट फिल्म क्रिटिक का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। जूरी ने उनकी गहरी रिसर्च, भारतीय सिनेमा की समझ और फिल्मों के सामाजिक व कलात्मक पक्ष पर लिखने की शैली की सराहना की। वहीं, नादिरुवुडे निम्मा कागी को सिनेमा पर सिनेमा पर बेस्ट बुक का अवॉर्ड का पुरस्कार मिला। जूरी का कहना है कि इस पुस्तक ने सिनेमा को नए नजरिए से समझाने का महत्वपूर्ण काम किया है। नॉन-फीचर फिल्म श्रेणी में इस साल 24 भाषाओं की 161 डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म और एनिमेशन फिल्मों का मूल्यांकन किया गया। जूरी ने बताया कि सभी फिल्मों में शानदार प्रतिभा देखने को मिली, जिससे विजेताओं का चयन आसान नहीं था। इस श्रेणी में 'Chola Dora aur Sui' (हिंदी) और 'Bhadra-Kali Natakam' (मलयालम) को स्पेशल जूरी मेंशन से सम्मानित किया गया। दोनों फिल्मों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रभावशाली ढंग से बड़े पर्दे पर पेश किया। बता दें इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा तय समय से करीब दो सप्ताह देर से हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जूरी को अंतिम निर्णय लेने और सभी पर विस्तार से विचार करने में अतिरिक्त समय लगा। इसके अलावा कुछ जूरी सदस्यों के व्यस्त कार्यक्रम भी देरी का कारण बने।

सोनम वांगचुक विवाद पर डिंपल यादव का हमला, बोलीं- लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबा रही है सरकार

सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाने पर सपा सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। वहीं, प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई का विरोध किया, जबकि पुलिस ने इसे हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत उठाया गया कदम बताया।

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा जबरन अस्पताल ले जाने की घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने केंद्र सरकार और पुलिस की इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इसे लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने वाला कदम करार दिया। डिंपल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि, 'बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि...जब शांतिपूर्ण तरीके से उठाई जा रही आवाजों को जबरन दबाया जाता है तो इससे सीधे तौर पर हमारे संविधान और लोकतंत्र को गहरी चोट पहुंचती है। सपा सांसद ने सख्त लहजे में कहा कि सोनम वांगचुक जैसे लोगों की आवाज को दबाना असल में देश की आत्मा को दबाने जैसा है।' आपको बता दें कि सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वह पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लगातार अनशन की वजह से उनका वजन काफी कम हो गया है और तबीयत बिगड़ रही थी। शनिवार सुबह पुलिस उन्हें वहां से सफदरजंग अस्पताल ले गई। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद अन्य प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस वांगचुक को जबरदस्ती घसीट कर ले गई और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की कमान 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके ने संभाल ली है। वांगचुक को हटाए जाने से नाराज दीपके ने शनिवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से पीछे नहीं हटने की अपील करते हुए कहा कि 20 जुलाई को होने वाला मार्च तय समय पर ही होगा। उन्होंने लोगों से भारी संख्या में जंतर-मंतर पहुंचने की अपील की है और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वांगचुक को हटाकर बड़ी गलती की गई है और अब यह आंदोलन और बड़ा होगा। सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने कहा था कि वांगचुक का हर रोज मेडिकल चेकअप कराया जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत इलाज मुहैया कराया जाए। माना जा रहा है कि इसी आदेश का पालन करते हुए पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर गई थी लेकिन अब इस पूरे मामले ने एक बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है और विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गए हैं।

यूपी की 3 विधानसभा सीटों पर नहीं होंगे उपचुनाव, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश की घोसी, दुद्धी और फरीदपुर विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव नहीं होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय बचा है, इसलिए इन रिक्त सीटों पर अलग से मतदान नहीं कराया जाएगा। अब इन तीनों क्षेत्रों के मतदाताओं को अपना नया विधायक चुनने के लिए अगले आम विधानसभा चुनाव का इंतजार करना होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब एक साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में इन तीनों रिक्त सीटों पर अलग से उपचुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण आयोग ने उपचुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है। उनके इस बयान के बाद घोसी, दुद्धी और फरीदपुर सीटों पर उपचुनाव की सभी अटकलों पर विराम लग गया है। अब इन सीटों के मतदाता सीधे अगले विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह जानकारी लखनऊ स्थित भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन के दौरान दी। इस मौके पर उन्होंने आयोग की हाल की चुनावी गतिविधियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग पिछले कुछ महीनों से विभिन्न चुनावी प्रक्रियाओं में व्यस्त था। पहले उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान 10 अप्रैल तक चलाया गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के चुनाव और अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों के कारण आयोग लगातार व्यस्त रहा।

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए रोजगार का मौका, इंटरनेशनल एकेडमिक काउंसलर पद पर भर्ती शुरू

युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में लखनऊ विश्वविद्यालय लगातार नए प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल (मुख्य परिसर) ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी ग्लोबल आर्कस-स्टडी इन इंडिया के लिए इंटरनेशनल एकेडमिक काउंसलर (फुल-टाइम) पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इस भर्ती के माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को एक ऐसे क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर मिलेगा, जिसकी मांग देश और विदेश दोनों स्तरों पर तेजी से बढ़ रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यह भर्ती अभियान कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी के मार्गदर्शन तथा प्लेसमेंट सेल (मुख्य परिसर) के निदेशक प्रो. अनूप कुमार भारतीय के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें अंतरराष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। लखनऊ विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट सेल पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से रोजगारपरक गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। समय-समय पर आयोजित कैंपस प्लेसमेंट, करियर काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप और भर्ती अभियानों के माध्यम से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इसी कड़ी में अब ग्लोबल आर्कस-स्टडी इन इंडिया के साथ यह भर्ती अभियान आयोजित किया जा रहा है, जिससे युवाओं को शिक्षा परामर्श और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सेवाओं के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने का अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार इस पद के लिए किसी भी विषय से स्नातक (Graduate) या स्नातकोत्तर (Postgraduate) अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए खुली है। हालांकि, कंपनी ने ऐसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की बात कही है जिनकी अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ हो, संप्रेषण कौशल उत्कृष्ट हो और छात्रों तथा अभिभावकों से प्रभावी संवाद स्थापित करने की क्षमता हो। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की जानकारी रखने वाले अभ्यर्थियों को भी वरीयता मिल सकती है।

ODOP योजना के तहत लखनऊ में सुनहरा मौका,

चिकनकारी और ज़री-जरदोज़ी कारीगरों से आवेदन आमंत्रित

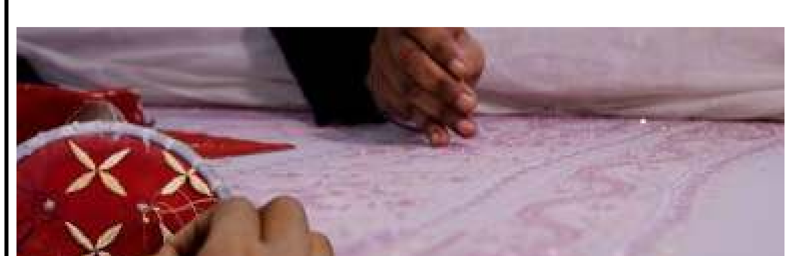

उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'एक जनपद, एक उत्पाद (ODOP)' योजना के तहत लखनऊ जनपद के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े कारीगरों और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र, लखनऊ ने चिकनकारी एवं ज़री-जरदोज़ी ट्रेड से जुड़े कारीगरों तथा इच्छुक युवक-युवतियों से 31 जुलाई 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ-साथ आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे अपने हुनर को और अधिक निखार सकें तथा स्वरोजगार और रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकें। इस संबंध में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, लखनऊ के उपायुक्त उद्योग अभिजीत गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल पारंपरिक उत्पादों का संरक्षण करना नहीं, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित कार्यबल और बेहतर बाजार उपलब्ध कराकर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना भी है। इसी सोच के तहत ओडीओपी प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना संचालित की जा रही है। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि योजना के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को केवल सामान्य प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि बेसिक और एडवांस स्तर का तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा आधुनिक डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, उत्पादन तकनीक, फिनिशिंग, उत्पाद की पैकेजिंग तथा बाजार की वर्तमान मांग के अनुरूप कार्य करने की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ हस्तशिल्प क्षेत्र में भी नई तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का उपयोग आवश्यक हो गया है।

राम मंदिर दान मामले की जांच निर्णायक मोड़ पर, SIT मांगेगी अतिरिक्त समय

अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर से जुड़ी कथित दान राशि में गड़बड़ी के मामले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने मामले की अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त समय मांगा है। सूत्रों के अनुसार, जांच टीम 20 जुलाई (सोमवार) को इस मामले में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी, जबकि विस्तृत और अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए अभी और समय की आवश्यकता जताई गई है। इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जांच टीम कई पहलुओं की गहन जांच कर रही है। दान राशि से जुड़े दस्तावेजों, बैंक लेन-देन, रिकॉर्ड, संबंधित व्यक्तियों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का मिलान किया जा रहा है, ताकि अंतिम रिपोर्ट पूरी तरह तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हो। यही वजह है कि SIT ने जल्दबाजी में निष्कर्ष देने के बजाय विस्तृत जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।

मानसून सत्र से पहले मायावती का सरकार पर हमला, संसद में जनहित के मुद्दों पर चर्चा की मांग

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सत्र शुरू होने से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर देश के कई ज्वलंत मुद्दों को उठाते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने चिंता जताई है कि क्या हर बार की तरह यह सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा या फिर देश की असली समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा होगी। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से जनहित के मुद्दों पर एकजुट होकर काम करने की अपील की है। मायावती ने कहा कि देश इस वक्त जबरदस्त महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है और महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक होने से युवाओं में भारी आक्रोश है। उन्होंने मांग की है कि संसद में इन मुद्दों से उत्पन्न माहौल को शांत करने और इनके संतोषजनक समाधान के लिए सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने अयोध्या के श्री राम मंदिर का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हेराफेरी और गबन को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। इस घटना ने यूपी समेत पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मायावती ने धर्म का राजनीतिकरण करने वालों को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जनता उनसे जवाब मांग रही है जिसकी गूंज सड़कों से लेकर अदालत तक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संसद में भी यह मुद्दा जरूर गूंजेगा और लोगों की इस पर पैनी नजर है। मायावती ने कई राज्यों की कानून व्यवस्था और सरकारी रवैये पर भी निशाना साधा। उन्होंने बंगाल में चुनाव के बाद के हालात और राजस्थान में लापरवाही के कारण गर्भवती महिलाओं की मौत पर गहरी चिंता जताई। इसके अलावा उन्होंने चुनावी रेवड़ियों में भारी गड़बड़ी, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, पुलिस मुठभेड़ के बढ़ते चलन और वर्षों से बसे लोगों की कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई को संविधान की जनकल्याणकारी व्यवस्था के खिलाफ बताया।

उन्नाव में 'पैराडाइज ऑफ यूपी 2026 सीजन-3' का भव्य आयोजन

उन्नाव के शिवा इन होटल में शनिवार को 'पैराडाइज ऑफ यूपी 2026 सीजन-3' का भव्य आयोजन किया जाएगा। राइजिंग स्टार एकेडमी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिले और आसपास के क्षेत्रों से लगभग 150 प्रतिभागी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10 बजे होगा। इसमें सदर विधायक पंकज गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि युवा नेता विनय सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। आयोजकों का उद्देश्य युवाओं और उभरती प्रतिभाओं को अपनी कला व हुनर प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस आयोजन में मॉडलिंग, ब्राइडल कॉम्पिटिशन, मेहंदी, मेकअप और डांस जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। प्रतिभागी अपनी रचनात्मकता, आत्मविश्वास और कला का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में फैशन और ग्लैमर से जुड़ी कई आकर्षक प्रस्तुतियां भी देखने को मिलेंगी। प्रसिद्ध मॉडल और डांसर कनिष्का त्रिवेदी भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। उनकी मौजूदगी से प्रतिभागियों में खासा उत्साह है। आयोजकों के अनुसार, कनिष्का प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करेंगी और अपने अनुभव साझा करेंगी। कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद तौफ़ीक़ और मॉडल सौम्या हैं, जबकि पूरे आयोजन का संचालन लक्ष्य निगम करेंगे। आयोजक मोहम्मद तौफ़ीक़ ने बताया कि 'पैराडाइज ऑफ यूपी' सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि प्रतिभाओं को पहचान दिलाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें फैशन, कला तथा मनोरंजन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करते हैं। मॉडल और डांसर कनिष्का त्रिवेदी ने भी कहा कि ऐसे मंच नई प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर देते हैं। उन्होंने जोर दिया कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के दम पर कोई भी युवा अपने सपनों को साकार कर सकता है। आयोजकों के अनुसार, प्रतिभागियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन विशेषज्ञ निर्णायक मंडल द्वारा किया जाएगा और विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है।

उन्नाव में पांच बीडीओ को मिला अतिरिक्त प्रभार, सीडीओ ने जारी किए आदेश

उन्नाव जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ने शुक्रवार रात पांच खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को अतिरिक्त प्रभार सौंपने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। संबंधित अधिकारियों को शीघ्र अतिरिक्त प्रभार ग्रहण कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीडीओ कृतिराज द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रिक्त पड़े विकास खंडों में प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए कार्यवाहक व्यवस्था के तहत यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य करने वाले अधिकारियों को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन या भत्ता देय नहीं होगा। जारी आदेश के तहत, सफीपुर के खंड विकास अधिकारी जानेंद्र सिंह यादव को फतेहपुर-84 विकास खंड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी प्रकार, सुमेरपुर की खंड विकास अधिकारी दीपशिखा वर्मा को बीघापुर विकास खंड का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। वहीं, बांगरमऊ के खंड विकास अधिकारी पंकज कुमार गौतम को गंजमुरादाबाद विकास खंड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, नव चयनित खंड विकास अधिकारी आर. राधा और रवि कुमार राय शर्मा को उनकी मूल तैनाती वाले विकास खंडों में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्नाव एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ट्रक की टक्कर से HAL कर्मचारी की मौत

उन्नाव में ट्रक की टक्कर से कार सवार HAL कर्मचारी की मौत हो गई। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह करीब 7 बजे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में हादसा हो गया। जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार की मौत हो गई। वह बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पद पर तैनात था। वह लखनऊ से अपने पैतृक गांव जा रहे थे। हादसे की सूचना पर यूपीडा की पेट्रोलिंग टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत हसनगंज सीएचसी ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी क्षेत्र के ही एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच शुरू कर दी है। मामला जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे का बताया जा रहा है। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर हादसा हुआ। जहां उन्नाव कबीरपुर के रहने वाले अंकित कनौजिया (38) मारुति सुजुकी से अपने पैतृक गांव खंभौली जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी ट्रक की टक्कर से मौत हो गई। वह बेंगलुरु में HAL में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के तौर पर काम करते थे। 8 साल पहले उनकी शादी रुचि कन्नौजिया (36) से हुई थी। उनकी एक 6 साल की मासूम बेटी अविका है। पत्नी रुचि हसनगंज तहसील क्षेत्र के ही शाहपुर तोंदा गांव के प्राथमिक विद्यालय में एक टीचर के रूप में तैनात हैं।

गंगाघाट में ईओ का औचक निरीक्षण, लापरवाही पर कर्मचारियों को फटकार

उन्नाव के गंगाघाट नगर पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी (ईओ) डॉ. राजेश कुमार ने शनिवार शाम नगर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था, नाला-नालियों की सफाई और मार्ग प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों को फटकार लगाई गई, वहीं अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को भी सख्त चेतावनी दी गई। ईओ डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि सुबह छह बजे भी नगर पालिका की विभिन्न सेवाओं का औचक निरीक्षण किया गया। इसमें सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच के साथ मोहल्लों, मुख्य मार्गों, नालों और नालियों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर सफाई कार्य में देरी और एक नाले में कूड़ा जमा मिला। इस पर सफाई नायक बच्चालाल को मौके पर ही कड़ी फटकार लगाते हुए कार्य में सुधार के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान मार्ग प्रकाश व्यवस्था की भी जांच की गई। स्विच मैन के कार्यों का सत्यापन करते हुए पाया गया कि कुछ स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें समय पर चालू या बंद नहीं की जा रही थीं। संबंधित स्विच मैन को अंतिम चेतावनी देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भविष्य में लापरवाही मिलने पर उन्हें सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, नगर पालिका परिसर में खड़े वाहनों का भी निरीक्षण किया गया और चालकों को नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य मार्ग पर करीब दो दर्जन दुकानदारों द्वारा साइकिल पथ पर अतिक्रमण का मामला भी सामने आया। ईओ ने मौके पर ही दुकानदारों को साइकिल ट्रैक के पीछे दुकानें लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो संबंधित दुकानदारों से जुर्माना वसूला जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिशाषी अधिकारी ने जोर देकर कहा कि नगर की सफाई, प्रकाश व्यवस्था और यातायात को सुचारु बनाए रखना नगर पालिका की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैंक ऑफ इंडिया की किसान गोष्ठी में 35 किसानों को 18.75 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृति पत्र

उन्नाव में बैंक ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीयकरण दिवस के उपलक्ष्य में संचालित कृषि माह कार्यक्रम के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान जिले के 35 किसानों को कुल 18.75 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। बैंक के प्रधान कार्यालय से आए वरिष्ठ अधिकारियों ने किसानों से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनीं और बैंकिंग सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने का भरोसा दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एलएमडी आर.के. गौतम ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीयकरण दिवस के अवसर पर कृषि माह का आयोजन करता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आवश्यकताओं को समझना, उन्हें समय पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना और केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना है। उन्होंने कहा कि बैंक किसानों को केवल ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें आधुनिक बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय जागरूकता से भी जोड़ने का कार्य कर रहा है। आर.के. गौतम ने बताया कि किसान गोष्ठी के माध्यम से किसानों को कृषि वित्त, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), फसल ऋण और विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाती है। इससे किसान अपनी जरूरतों के अनुरूप योजनाओं का लाभ लेकर खेती को अधिक लाभकारी और आधुनिक बना सकते हैं। बैंक के एक प्रबंधक ने बताया कि कृषि माह अभियान के तहत प्रधान कार्यालय की टीम उन्नाव पहुंची है। उन्होंने किसानों से बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि बैंक से जुड़े किसानों को आसान ऋण, सरकारी सब्सिडी आधारित योजनाओं और अन्य वित्तीय सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकता है।

गंगाघाट की पोनी रोड पर भारी पुलिस बल के बीच चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

उन्नाव के गंगाघाट क्षेत्र की पोनी रोड पर सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शनिवार को शुरू हुई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर की मदद से सड़क की जद में आ रहे मकानों और अन्य निर्माणों को हटाया गया। यह कार्रवाई शुक्रवार को स्थानीय लोगों के विरोध के कारण रोकनी पड़ी थी। हालांकि, शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की टीम ने अभियान को आगे बढ़ाया। पोनी रोड के चौड़ीकरण को लेकर बीते रविवार को हुई बैठक में नौ मीटर के बजाय आठ मीटर चौड़ी सड़क बनाने पर सहमति बनी थी। इसी निर्णय के अनुपालन में शुक्रवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर नवीन मंत्रा जेसीबी मशीन और अन्य कर्मचारियों के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। जैसे ही टीम ने कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। पीडब्ल्यूडी के जेई नवीन मंत्रा ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए टीम के साथ गाली-गलौज और अभद्रता की। इसके बाद कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और पुलिस को घटना की सूचना दी गई। प्रशासन ने शनिवार को व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के साथ अभियान चलाने की तैयारी की। सुबह करीब 11 बजे पीडब्ल्यूडी की टीम बुलडोजर और अन्य संसाधनों के साथ दोबारा मौके पर पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। पुलिस की निगरानी में सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। अधिकारियों ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण का उद्देश्य क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना और लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या का समाधान करना है। कार्रवाई के दौरान राजस्व और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और पूरे अभियान की निगरानी करते रहे। प्रशासन ने कहा है कि यह परियोजना जनहित से जुड़ी है और इसे निर्धारित मानकों के अनुसार पूरा कराया जाएगा।

राम मंदिर चंदा चोरी मामला

सपा का सीएम योगी पर हमला, जिम्मेदारी लेने की मांग

मुरादाबाद में सपा सांसदों ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में मुख्यमंत्री योगी से जवाबदेही की मांग की। आठ आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि पुलिस नकदी, आभूषण और संपत्तियों की जांच कर रही है।

राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। मुरादाबाद पहुंचे सपा सांसद सनातन पांडे ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को राम मंदिर चोरी मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं, आंवला सांसद नीरज मौर्य ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई, चढ़ावे का नियमित हिसाब जनता के सामने रखने और धनराशि को जनकल्याण के कार्यों में लगाने की मांग की। मुरादाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद सनातन पांडे ने CM योगी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे हेलीकॉप्टर कितनी बार गया और कितनी बार लौटा। चोरी उनकी नाक के नीचे हो रही थी। मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। वहीं सांसद नीरज मौर्य ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे चोरी से पूरा देश आहत हुआ है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे हर सप्ताह जनता के सामने चढ़ावे का हिसाब रखा जाए और इस धनराशि का उपयोग जनकल्याण के कार्यों में किया जाए। जांच अधिकारियों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में गिरफ्तार आठ आरोपियों में से छह आरोपी दान किए गए रुपये अपने कपड़ों, जेबों और जूतों में छिपाते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिस ने 25 जून को ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करूणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव शामिल हैं। जांच में सामने आया कि टिन्नू यादव पहले चंपत राय का चालक रह चुका है और मंदिर के दानपात्रों की निगरानी करता था, जबकि मनीष यादव चढ़ावे की गिनती में शामिल था। पुलिस पहले ही टिन्नू के घर से एक लाख रुपये और मनीष के घर से दो लाख रुपये बरामद कर चुकी है। रिमांड के दौरान दोनों आरोपियों से पूछताछ कर अतिरिक्त नकदी, आभूषण और इस धन से खरीदी गई संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है। जांच के दौरान पूर्व बैंक कर्मचारियों सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा से पूछताछ के आधार पर पुलिस नकदी, आभूषण और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी अदालत में पेश कर चुकी है। जून के पहले सप्ताह में सामने आए इस कथित चंदा चोरी मामले में अब तक आठ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि ट्रस्ट के दो वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस्तीफा भी दे दिया है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल एकेडमिक काउंसलर पद पर भर्ती

युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में लखनऊ विश्वविद्यालय लगातार नए प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल (मुख्य परिसर) ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी ग्लोबल आर्कस-स्टडी इन इंडिया के लिए इंटरनेशनल एकेडमिक काउंसलर (फुल-टाइम) पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इस भर्ती के माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को एक ऐसे क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर मिलेगा, जिसकी मांग देश और विदेश दोनों स्तरों पर तेजी से बढ़ रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यह भर्ती अभियान कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी के मार्गदर्शन तथा प्लेसमेंट सेल (मुख्य परिसर) के निदेशक प्रो. अनूप कुमार भारतीय के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें अंतरराष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। लखनऊ विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट सेल पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से रोजगारपरक गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। समय-समय पर आयोजित कैंपस प्लेसमेंट, करियर काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप और भर्ती अभियानों के माध्यम से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इसी कड़ी में अब ग्लोबल आर्कस-स्टडी इन इंडिया के साथ यह भर्ती अभियान आयोजित किया जा रहा है, जिससे युवाओं को शिक्षा परामर्श और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सेवाओं के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने का अवसर मिलेगा।

बलरामपुर के किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन शुरू

बलरामपुर के किसानों के लिए राहत और आधुनिक खेती की दिशा में बड़ी पहल हुई है। कृषि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। किसान 10 अगस्त की मध्यरात्रि तक आवेदन कर ड्रोन, पावर टिलर, कंबाइन हार्वेस्टर समेत कई कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ ले सकते हैं। विभाग ने समय रहते आवेदन करने की अपील की है। बलरामपुर जिले में खेती को आधुनिक और कम लागत वाला बनाने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत संचालित इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग 16 जुलाई से शुरू हो चुकी है। जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 की रात 12 बजे निर्धारित की गई है। उप कृषि निदेशक श्याम नारायण राम ने बताया कि जिले के पात्र किसान विभागीय पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वे अपने निकटतम जनसेवा केंद्र या कृषि विभाग के कार्यालय से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM) योजना के तहत किसानों को कई आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। इनमें रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, पावर टिलर, पावर वीडर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, लेजर लैंड लेवलर, किसान ड्रोन और कंबाइन हार्वेस्टर प्रमुख हैं। इसके अलावा ग्रामीण उद्यमियों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

CM योगी ने भूमि दान करने वाले RSS स्वयंसेवक राजपाल सिंह को किया सम्मानित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बुलंदशहर का दौरा किया। यहां उन्होंने विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जिनका समाज और शिक्षा के प्रति समर्पण सबके लिए प्रेरणा बन गया है। मुख्यमंत्री ने शिकारपुर स्थित 'रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर' के लिए अपनी निजी भूमि दान करने वाले वरिष्ठ स्वयंसेवक राजपाल सिंह को मंच पर अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। राजपाल सिंह शिकारपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के काफी पुराने और वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं। उनकी अपनी कोई संतान नहीं है। समाज और देश के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका को समझते हुए उन्होंने अपनी निजी जमीन रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर के निर्माण के लिए दान कर दी। उनके इस बड़े कदम को शिक्षा और राष्ट्र सेवा के प्रति एक बहुत बड़ी मिसाल माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से उनकी जमकर तारीफ की और कहा कि ऐसे काम समाज के लिए बेहद प्रेरणादायक हैं और आने वाली पीढ़ियों को समाज हित में काम करने की सीख देते हैं। स्कूल के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने बुलंदशहर और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 58 विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। इनमें 27 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई और 31 का उद्घाटन किया गया। इन सभी विकास परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 574 करोड़ रुपये है। इनमें सड़क निर्माण, पेयजल योजना, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पुलिस बैरक, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आईटीआई, स्पोर्ट्स स्टेडियम और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल जैसी अहम सुविधाएं शामिल हैं। इससे जिले में रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।